BANDARU DATTATREYA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Departmental Council (JCM) of this Ministry, which is the national level machinery, is not functioning at present. Since no definite proposals have been firmed up, it would be pre-mature to comment on the modalities to be adopted.

राजगढ़ में पेयजल के लिए राजीव गांधी मिशन

2897. **श्री राघवजी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्हें राजगढ़ जिले में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत मिशन का कार्य प्रारम्भ होने के बाद से आज तक राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी-कितनी राशि दी गई, कार्य और राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के गैर-सरकारी संगठनों से कार्य न कराने के एकमत प्रस्ताव के बाद भी उन्हीं से कार्य करवाया जा रहा जिससे भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है और जन-प्रतिनिधियों की कोई सहभागिता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

DDA's Expandable House Scheme, 1996

2898. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the DDA has launched the Expandable Housing Scheme in 1996;

(b) if so, the number of persons who were allotted and those who actually took possession, area-wise;

(c) whether basic facilities like water, electricity, approach roads were created before providing such allotment;

(d) if so, the details thereof;

(e) if not, the reasons and when such facilities are likely to be provided;

(f) whether DDA has been charging interest on instalment to be paid by allottees without providing such facilities; and

(g) if so, the justification for such charges?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) and (b) Yes, Sir. The information regarding number of flats allotted and possession taken over is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) to (e) The availability of basic facilities like electricity, water & approach roads is as detailed as below:—

(i) ELECTRICITY: External electrical services are to be provided by Delhi Vidyut Board for which DDA is continuously pursuing and monitoring for expeditious provision of the same. The target dates of electrification as given by DVB is indicated in statement (*See* below).

(ii) WATER SUPPLY: In the absence of water from Delhi Jal Board the same has been made available as an interim arrangement through tube-wells which can only be commissioned when Electricity is provided by the Delhi Vidyut Board.

(iii) APPROACH ROADS: Approach roads are available.

(f) and (g) No. Sir.

(i) In the case of hire-purchase allotments commencement of monthly instalments are deferred till services become available.

(ii) In case of cash-down allotments, interest on delayed payment of the amount representing 50% of the demanded amount is waived off, till the date of payment or the date when services become available, whichever is earlier.

Statement

S. No.	Locality	Block/Pkt. Area	Target Date of Electrification as given by DVB on 13.6.98 & 30.6.98
1. Rohini	Sector 21	Pkt. 4, Ph. III	8/98
	Sector 22	Pkt. 12, Ph, III	9/98
		Pkt. 16, Ph, III	9/98
		Pkt. 16, Ph, III	9/98
		Pkt. 17, Ph, III	9/98
		Pkt. 15, Ph, III	10/98
	Sector 24	Pkt. 10, Ph, III	11/98
		Pkt. 13, Ph, III	11/98
		Pkt. 25, Ph, III	11/98
		Pkt. 26, Ph, III	11/98
		Pkt. 1, Ph, III	10/98
	Sector-25	Pkt. 1, Ph. III	Target not given likely to be completed by 2/99
		Pkt. 8, Ph. III	-do-
		Pkt. 9, Ph. III	-do-
4. Dwarka (57 MIG+119 LIG) (57 MIG+119 LIG)		Sector-13 PH. II	9/98
		Phase, I	9/98

प्राइवेट भवन निर्माताओं द्वारा मकानों का निर्माण

2899. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अब प्राईवेट भवन निर्माताओं को मकान निर्माण और विक्रय की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा में उल्लेखानुसार दो मिलियन अतिरिक्त मकानों का निर्माण करने के लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में आवास उद्योग में प्राइवेट सैक्टर को शामिल किया जाए। इस बारे में दिनांक 19.6.1998 को जारी आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इकट्ठी न्यूनतम 30 एकड़ भूमि इसके लिए अपेक्षित होगी, व्यक्तियों का स्वामित्व वैध होना चाहिए, विकास कर्त्ता को सम्पूर्ण क्षेत्र के बाजार मूल्य का 20% आश्रय कोष में जमा करना होगा और 10% आवास ई०डब्ल्यू एस० तथा एल०आई०जी० वर्ग के लिए होंगे।

Housing Shortage in Urban Areas

2900. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the acute housing shortages in the country, particularly in the urban areas;

(b) if so, the steps taken by Government to resolve the housing problems;